ओबामा भारत में : लेकिन ध्यान है पाकिस्तान पर
Obama in India: Pakistan on the Mind

ब्रूस राइडेल
Bruce Riedel
October 25, 2010

बैराक हुसैन ओबामा भारत यात्रा पर आने वाले छठे और क्रमिक रूप में तीसरे अमरीकी राष्ट्रपति हैं. वे अपने पहले कार्यकाल की पहली छमाही में यहाँ आ रहे हैं. उनसे पहले जिमी कार्टर और रिचर्ड निक्सन इस प्रकार यहाँ आए थे. यद्यपि राष्ट्रपति के दौरे बहुत सावधानी से नियोजित और तय होते हैं, लेकिन घटनाचक्र कार्यसूची को कभी-भी प्रभावित कर सकता है.
राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमरीका अफ़गानिस्तान में अपना सबसे लंबा युद्ध लड़ रहा है और प्राकृतिक विपदा में बुरी तरह फँसे पड़ोसी देश पाकिस्तान को पटरी पर लाने के लिए भारी प्रयास में जुटा है. नई दिल्ली में होने वाली चर्चा के पीछे मुख्यतः अफ़गान युद्ध और पाकिस्तान का भविष्य छाया रहेगा.

ड्वैट आइज़नहॉवर पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने एक खास तरह के परिप्रेक्ष्य की पेशकश के लिए दक्षिण एशिया का दौरा किया था. वे सन् 1959 में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरे पर आए थे. आइज़नहॉवर ने पाकिस्तान के साथ दो पश्चिमी संधियों -सैंटो और सिएटो- पर हस्ताक्षर किए थे और पेशावर में यू 2 के गुप्त बेस पर एक समझौता किया था ताकि पाकिस्तान के पहले सैनिक तानाशाह अयूब खान के साथ मिलकर सोवियत संघ की जासूसी की जा सके. परंतु वे जवाहर लाल नेहरू के साथ भी मिलकर काम करना चाहते थे, जिन्होंने गैटिसबर्ग में उनके पारिवारिक फ़ार्म का दौरा किया था. इसलिए आइज़नहॉवर ने खान के साथ अपने प्रशासन के नज़दीकी संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत का चार दिनों का दौरा किया था.

रिचर्ड निक्सन ने सन् 1969 में भारत में आधे से भी कम दिन गुज़ारा था. कदाचित् अमरीकी इतिहास में वह पहले सर्वाधिक पाकिस्तान समर्थक राष्ट्रपति थे, वे इंदिरा गाँधी से नफ़रत करते थे और सन् 1971 में वे पूरी तरह पाकिस्तान की ओर झुक गए थे. लगभग एक दशक के बाद सन् 1971 में कार्टर भारत आए. उन्होंने अनजाने में ही सीधे माइक्रोफ़ोन पर कुछ अराजनीतिक टिप्पणी कर दी, वही तीन दिन के उनके दौरे की मुख्य सुर्खी बन गई. उसके बाद वे जनरल ज़िया द्वारा ज़ुल्फिकार भुट्टो को फाँसी पर

चढ़ाने के विरोध स्वरूप पाकिस्तान में बिना रुके ही ऊपर से उड़कर वापस चले गए और वे ईरान का दौरा करने वाले अमरीका के अंतिम राष्ट्रपति हो गए. अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा को अब पच्चीस साल हो गए हैं.

बिल क्लिंटन भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन भारत में लगातार सरकार बदलने के कारण और सन् 1998 में इसके परमाणु परीक्षण के कारण यह संभव न हो सका. सन् 1999 में कारगिल युद्ध के कारण पहली बार परिस्थितियों ने करवट ली और अमरीका पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गया. सन् 2000 में क्लिंटन के पाँच दिवसीय भारत प्रवास में अमरीकी-भारत भागीदारी का नया अध्याय शुरू हुआ और पाकिस्तान में उनके बिताए पाँच घंटों ने उनके बिगड़ते संबंधों का स्पष्ट संकेत दे दिया.

जॉर्ज डब्ल्यू बुश नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ही मज़बूत संबंध बनाने में कामयाब रहे. भारत के साथ उन्होंने नागरिक परमाणु शक्ति समझौता किया और जनरल मुशर्रफ़ को पूरा समर्थन दिया. भारत में उनके बिताए तीन दिन और पाकिस्तान में बिताई एक रात से उन्होंने दोनों देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया. इसी परमाणु समझौते के कारण भारत को परमाणु क्लब में प्रवेश मिला और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई.

ओबामा के पास परमाणु समझौते के आकार और परिमाण के बराबर की कोई पेशकश नहीं है,जिसे व्हाइट हाउस में “डिलीवरेबल” कहा जाता है. दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर समझौते होंगे, शायद बड़े पैमाने पर सी-17 वाहनों के लिए बड़ी मात्रा में हथियारों की बिक्री का समझौता हो सकता है और आतंकवाद से लड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मामलों पर नज़दीकी सहयोग की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया जा सकता है.

इसके बावजूद अमरीकी राष्ट्रपति,प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की नेता सोनिया गाँधी के बीच निजी बातचीत के दौरान पाकिस्तान ही छाया रहेगा, क्योंकि आज दक्षिण एशिया में सबसे ज्वलंत प्रश्न है पाकिस्तान का भविष्य. पाकिस्तान पूरे विश्व में सबके लिए ही सबसे खतरनाक देश बन गया है, खास तौर पर अमरीका और भारत के लिए. यह पूरी दुनिया में फैले जिहादी आंदोलन का मूल केंद्र बन गया है. इसीने सन् 2001 में न्यूयॉर्क पर और सन् 2008 में मुंबई पर हमला किया था. पाकिस्तानी सरकार के इरादे भले ही नेक हों, लेकिन यह एक कमज़ोर नागरिक सरकार है और यह देश की अनेक

समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है. सेना देश के अनेक भागों में जिहादी लोगों की संरक्षक है और शेष भाग में उनके साथ युद्ध में संलग्न है. इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे अधिक तेज़ी के साथ परमाणु हथियारों का जखीरा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है.

इन गर्मियों में आई बाढ़ ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है और उसकी समस्याएँ भी जगजाहिर हो गई हैं : कमज़ोर शासन, कमज़ोर बुनियादी ढाँचा और इस्लामी उग्रवादियों का बढ़ता आंदोलन. पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में कमज़ोर शासन ने इन चुनौतियों को और भीषण रूप दे दिया है. तालिबान का कैंसर अब दुरंद रेखा के दोनों ओर फैल चुका है. पाकिस्तानी सेना दक्षिणी भाग में उनके साथ युद्ध करती है और उत्तरी भाग में उनकी मदद करती है.

ओबामा का दौरा उस समय हो रहा है जब कश्मीर के सवाल ने फिर से सिर उठा लिया है. पाकिस्तान निश्चय ही इस असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास करेगा. राष्ट्रपति अपने दौरे में कश्मीर की चर्चा को टाल तो सकते हैं, लेकिन उस पर अगर वे कोई टिप्पणी करते हैं तो मामला विस्फोटक भी हो सकता है.

ओबामा और सिंह को चाहिए कि वे आपसी सहयोग के माध्यम से पाकिस्तान को ज़ेहादी दुःस्वप्न से बचाने का प्रयास करें. इसका समाधान बाहरी लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही इसे बाहर से नियंत्रित या अलग-थलग किया जा सकता है. निजी स्तर पर वरिष्ठ भारतीय अधिकारी भी यह मानते हैं कि वाशिंगटन और नई दिल्ली-दोनों के लिए ही इस समस्या का निदान एक ही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके लिए ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई है,जिससे कामयाबी मिलने की उम्मीद हो. इसका तत्काल समाधान ज़रूरी है, लेकिन इसका समाधान जादू का डंडा घुमाकर नहीं किया जा सकता. दोनों देश मानते हैं कि पाकिस्तान के सहयोग के बिना इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकती, लेकिन दोनों देश इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उनका सहयोग कारगर सिद्ध हो रहा है.

तीसरा दल पाकिस्तान का सहयोगी देश चीन भी हो सकता है. इसे निजी वार्ताओं में व्यापक तौर पर साथ लिया जा सकता है. ओबामा पाकिस्तान को मज़बूत करने के लिए क्षेत्रीय राजनय का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं. बीजिंग को इस प्रक्रिया में एक खिलाड़ी की तरह भाग लेना होगा.

हर लिहाज से ओबामा और सिंह के अच्छे कामकाजी संबंध हैं. उन्हें मिलकर गंभीर मंथन करना होगा कि वे दोनों मिलकर दक्षिण एशिया के इस बीमार देश को कैसे बचाएँ.

ब्रूस राइडेल ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में सीनियर फ़ैलो हैं और कैसी (उच्च भारतीय अध्ययन संस्थान) के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य हैं. उन्होंने ही सन् 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत के दौरे की योजना तैयार की थी.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<*malhotravk@hotmail.com*>